

राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ छेड़े गए युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से वैश्विक व्यापार प्रवाह को बाधित कर दिया है; और,

जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार, इस संघर्ष ने "वैश्विक बाजारों में तेल आपूर्ति की उपलब्धता को नाटकीय रूप से कम कर दिया है और तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसके व्यापक प्रभाव पड़े हैं" और,

जबकि, इलिनॉय में डीजल ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं; और,

जबकि, ईआईए का अनुमान है कि "मध्य पूर्व से तेल निर्यात पर प्रतिबंध वर्ष के अंत तक बने रहेंगे, जिससे इस क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन 2027 की दूसरी तिमाही तक संघर्ष-पूर्व औसत से नीचे रहेगा" और,

जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में आसुत ईंधन भंडार 2027 के अधिकांश समय तक पांच साल (2021 से 2025) के निचले स्तर से नीचे रहने का अनुमान है, जिससे डीजल ईंधन की कीमतों में और वृद्धि होगी; और,

जबकि, डीजल ईंधन की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप इलिनॉय में कृषि और कच्चे माल, जैसे कि गोमांस और अनाज, के परिवहन की लागत में असाधारण वृद्धि हुई है; और,

चूंकि, कृषि परिवहन की बढ़ी हुई लागत किराने के सामान की उंची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाली जाती है; और,

चूंकि, ट्रंप प्रशासन द्वारा पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) में की गई कटौती के कारण इलिनॉय के किसानों को लाभप्रदता में और अधिक नुकसान का खतरा है, जो इलिनॉय के पात्र निवासियों को स्थानीय रूप से उगाए गए भोजन को खरीदने के लिए एसएनएपी लाभों का उपयोग करने की अनुमति देता है; और,

जबकि, इलिनॉय के किसान अब अभूतपूर्व वित्तीय दबाव और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं; और,

जबकि, कृषि पूरे इलिनॉय के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक चालक है; और,

जबकि, इलिनॉय परिवहन विभाग (आईडीओटी) का इलिनॉय हार्वेस्ट परमिट (आईएचपी) कार्यक्रम प्रभावी रूप से, लेकिन केवल अस्थायी रूप से, प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक शरद ऋतु की फसल के मौसम के दौरान निर्दिष्ट मार्गों पर भारी ट्रक भार की अनुमति देता है; और,

जबकि, इलिनॉय के किसानों और कमजोर परिवारों के लिए डीजल ईंधन संकट से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए आपातकालीन कदम आवश्यक हैं; और,

जबकि, वर्तमान परिस्थितियाँ इलिनॉय निवासियों और राज्य के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आवश्यक ईंधन और ऊर्जा की गंभीर कमी के परिणामस्वरूप आपदा का गठन करती हैं, जिसके लिए राज्य द्वारा आपातकालीन कार्रवाई की आवश्यकता है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राज्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; और,

जबकि, ये परिस्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार आपदा की उद्घोषणा जारी करने को उचित ठहराती है; और,

जबकि, इलिनॉय संविधान के अनुच्छेद V, धारा 8 में यह प्रावधान है कि “[राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के निष्ठापूर्वक निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा]” और प्रस्तावना में कहा गया है कि इलिनॉय संविधान का केंद्रीय उद्देश्य “लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान करना” है;

अतः, इलिनॉय के लोगों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर, इलिनॉय राज्य का राज्यपाल, एतद्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा मौजूद है और राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 की धारा 7 के अनुसार प्रदत्त सभी आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग को अधिकृत करती है, जिसमें नीचे उल्लिखित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुभाग 2: इलिनॉय राजस्व विभाग, इलिनॉय राज्य पुलिस और आईडीओटी सहित राज्य एजेंसियों को इस आपदा घोषणा के तहत जारी किए गए किसी भी कार्यकारी आदेश को लागू करने और फसल कटाई के मौसम के दौरान डीजल की कमी और उच्च लागत को दूर करने के उपायों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

अनुभाग 3: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 आईएलसीएस 3305/7(1), (2) और (3) की धारा 7(1), (2) और (3) के अनुसार, यह घोषणा राज्यपाल के अधिकार, आवश्यकतानुसार, किसी भी नियामक क़ानून, नियम या विनियम के प्रावधानों को निलंबित करने के लिए; राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए; और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित करने या सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य विभागों और एजेंसियों या उनकी इकाइयों के निर्देशन, कर्मियों या कार्यों को स्थानांतरित करने के राज्यपाल के अधिकार को सक्रिय करती है।

अनुभाग 4: यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 6 अक्टूबर, 2026

राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 6 अक्टूबर, 2026